

**FORM G (THIRD)**  
**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**  
**M/S SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED OPERATING IN REAL ESTATE AT HARYANA**

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

<b>RELEVANT PARTICULARS</b>		
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/CIIN/LLP No.	SRS Real Infrastructure Limited CIN L65910HR1990PLC040431
2.	Address of the Registered Office	SRS Multiplex, Top Floor City Centre, Sector-12 Faridabad Haryana, 121007
3.	URL of website	<a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
4.	Details of Place where majority of fixed assets are located	Faridabad, Rewari, Panchkula, Palwal, Rohtak (All places are in State of Haryana)
5.	Installed capacity of main products/ services	Development and Construction of Commercial and Residential Projects.
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per the available, there is no operation of Corporate Debtor in last few years.
7.	Number of employees/ workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	The required details can be sought by E-mail at <a href="mailto:cirp.srsreal@gmail.com">cirp.srsreal@gmail.com</a> by submitting the confidential undertaking.
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2) (h) of code is available at:	The eligibility criteria can be downloaded from website <a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
10.	Last date for receipt of expression of interest	24-09-2023
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	04-10-2023
12.	Last date for submission of objections to provisional list	09-10-2023
13.	Process email id to submit EOI	<a href="mailto:cirp.srsreal@gmail.com">cirp.srsreal@gmail.com</a>



Sd/-

Amarpal

Resolution Professional of SRS Real Infrastructure Ltd  
IBBI/IPA-001/IP/ P-01584/2018-2019/12411  
AFA Valid Upto 23.11.2023

Address: E-11, Lower Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi-110014

Date 9<sup>th</sup> Septemebr, 2023  
Place: New Delhi

## शराब के लिए पैसा न देने पर कर दी थी दोस्त की हत्या

जनसत्ता संवाददाता  
नोएडा, 8 सितंबर।

बौद्धला टी प्लाइट के पास केबल की दुकान पर काम करने वाले युवक ने विवाद में ढाके पर काम करने वाले अपने दोस्त की सिर और मुँह पर ईंट से बार कर हत्या कर दी। शराब के रूप पर नहीं देने के चलते घटना को अंजाम दिया गया।

बताया गया है कि दोनों ने पहले शराब पी थी। आरोपी ज्ञादा शराब पीना चाहता था। लेकिन दोस्त ने दोनों से मना किया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन सुबह गहरीहों ने पुलिस को जानकारी दी। थाना स्कर्टर-49 पुलिस ने सर्विलांस की मदद से हायरोपी को गिरफतार कर लिया।

**नोएडा** के बौद्धला क्षेत्र का मामला, सिर पर किया था ईंट से बार, आरोपी शब को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया था।

एसीपी सौम्या सिंह ने बताया कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थुक था। पुलिस ने हत्यारे के कब्जे से बारदात में प्रयुक्त पत्तर (ईंट का हिस्सा) भी बरामद कर दिया है। बुलंदशहर का रहने वाला पिंड सिंह (31) बौद्धला गांव स्थित साईं डाबे पर काम करता था। केबल की दुकान पर काम करने वाले अमरोहा निवासी मोनू रिंग से उसकी दोस्ती थी। 6 सितंबर को रात करीब आठ बजे पिंड से दोबे से पांच सौ रुपए लिए और मोनू के साथ निकल गया। दोनों शराब के ठेके पर

पहुंचे। आरोप है कि यहां पर मोनू और पिंड के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बौद्धला टी प्लाइट के पास स्थित झाड़ियों के पास बार दोनों पहुंचे, तो मोनू ने शराब कर हत्या कर दी। आरोपी शब को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। पछताच और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मोनू को सेक्टर-47 की लालबत्ती से पिरफतार कर लिया।

पिंड पांच साल पहले रोजगार की तलाश में नोएडा आया था। कासाना सहित कई अन्य जगहों पर ढाके और होटल में उसने नौकरी की। फिलहाल में वह बौद्धला गांव स्थित डाबे पर नौकरी कर रहा था। पिंड के मातापिता की मौत हो चुकी है। भाई सहित घर के अन्य सदस्यों का खबर पिंड ही भेजता था।



जी-20 शिखर सम्मेलन स्थल पर लगी प्रदर्शनी में अपने कौशल का कमाल दिखाता एक कलाकार।

## कबाड़ी से रिश्वत मांगने वाला सिपाही बर्खास्त, जांच अधिकारी निलंबित

जनसत्ता संवाददाता  
ग्रेटर नोएडा, 8 सितंबर।

थाना रब्बुपुरा क्षेत्र के भाईपुर गांव में कबाड़ी की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से एक लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त ने आरोपी सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही मामले में जांच अधिकारी को भी निलंबित कर थाना रब्बुपुरा प्रभारी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। रिश्वत मांगने की आडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ था।

गैरतत्व है कि यहां दिनों रब्बुपुरा पुलिस ने चोरी का सामान खोदने के आरोप में एक कबाड़ी समृद्ध चार लोगों को जेल भेजा था। इस मामले में कुछ लोगों को रुपए लेकर छोड़ने का आरोप भी पुलिस पर लगा था। इसी प्रकार की आड़ में थाना रब्बुपुरा में नैनात सिपाही अधिकारी को भी दुकान चलाने वाले वर्सीम से एक लाख रुपए रिश्वत का मांगने के लिए और आरोपी को खोदा था।

गैरतत्व है कि यहां दिनों रब्बुपुरा पुलिस ने चोरी का सामान खोदने के आरोप में एक कबाड़ी समृद्ध चार लोगों को जेल भेजा था। इस मामले में कुछ लोगों को रुपए लेकर छोड़ने का आरोप भी पुलिस पर लगा था। इसी प्रकार की आड़ में थाना रब्बुपुरा में नैनात सिपाही अधिकारी को भी दुकान चलाने वाले वर्सीम से एक लाख रुपए रिश्वत का मांगने के लिए और आरोपी को खोदा था।

गैरतत्व है कि यहां दिनों रब्बुपुरा पुलिस ने चोरी का सामान खोदने के आरोप में एक कबाड़ी समृद्ध चार लोगों को जेल भेजा था। इस मामले में कुछ लोगों को रुपए लेकर छोड़ने का आरोप भी पुलिस पर लगा था। इसी प्रकार की आड़ में थाना रब्बुपुरा में नैनात सिपाही अधिकारी को भी दुकान चलाने वाले वर्सीम से एक लाख रुपए रिश्वत का मांगने के लिए और आरोपी को खोदा था।

## 'ग्रैप' को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर

जनसत्ता संवाददाता  
ग्रेटर नोएडा, 8 सितंबर।

एक अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉस प्रक्षण प्लान (ग्रैप) को लेकर जिला संसद भारती उच्च न्यायालय से कहा है कि उसके बाद नोएडा उच्च न्यायालय से कहा है कि उसके बाद नोएडा उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी में आग्रह किया है कि महिला चिकित्सक के 51,97,329 रुपए के चिकित्सा बिल के बुगतान करने में मदद की जाए। चूंकि भागवनानी अपनी यादवाशत खो चुकी हैं और उनकी देखभाल के लिए आवश्यक रिश्वेदार आगे नहीं आया है, ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल एक अदालत मित्र नियुक्त किया था। अदालत ने इहबास से रोगी की रिश्ति का परीक्षण करने और उपाय सुझाव को भी कहा।

उन्हें अभिभावक नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया था।

मूलचंद अस्पताल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि उसके बाद नोएडा उच्च न्यायालय की अजाइम्य रोगी 84 वर्षीय एक चुरी रोगी विशेषज्ञ की रिश्ति विगड़ गई है। अस्पताल ने अदालत से इस मरीज के करीब 16 लाख रुपए के चिकित्सा बिल के बुगतान में मदद मांगी है।

सुंदरी जीवनानी को 2017 में उनके भाई अस्पताल लेकर आए थे जिनका अपनी एक याचिका के लंबित रहने के द्वारा निधन हो गया था। भागवनानी के भाई ने अदालत से अपनी बहन के स्वास्थ्य की देखभाल करने एवं मैडिकल बिल का भुगतान करने के लिए

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 सितंबर।

एक अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉस प्रक्षण प्लान (ग्रैप) को लेकर जिला संसद भारती उच्च न्यायालय से कहा है कि उसके बाद नोएडा उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी में आग्रह किया है कि महिला चिकित्सक के 51,97,329 रुपए के चिकित्सा बिल का भुगतान करने में मदद की जाए। चूंकि भागवनानी अपनी यादवाशत खो चुकी हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई रिश्वेदार आगे नहीं आया है, ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल एक अदालत मित्र नियुक्त किया था। अदालत ने इहबास से रोगी की रिश्ति का परीक्षण करने और उपाय सुझाव को भी कहा।

साथ ही एकल इस्तेमाल योग्य पालिथीन के उपयोग को कम करने के लिए नगर नियमाय और प्राधिकरणों के स्तर से कपड़े के थैले आदि बाटे जाने की जरूरी बताया। साथ ही पालिथीन की थैली का उपयोग करने वालों पर जुमाना लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कहा है। एनजीटी व प्रदूषण कंटेनर बोर्ड के मालियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण एवं गंगा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

साथ ही एकल इस्तेमाल योग्य पालिथीन के उपयोग को कम करने के लिए आदि बाटे जाने की जरूरी बताया। साथ ही पालिथीन की थैली का उपयोग करने वालों पर जुमाना लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कहा है। एनजीटी व प्रदूषण कंटेनर बोर्ड के मालियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण एवं गंगा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

साथ ही एकल इस्तेमाल योग्य पालिथीन के उपयोग को कम करने के लिए आदि बाटे जाने की जरूरी बताया। साथ ही पालिथीन की थैली का उपयोग करने वालों पर जुमाना लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कहा है। एनजीटी व प्रदूषण कंटेनर बोर्ड के मालियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण एवं गंगा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 8 सितंबर।

एक अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉस प्रक्षण प्लान (ग्रैप) को लेकर जिला संसद भारती उच्च न्यायालय से कहा है कि उसके बाद नोएडा उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी में आग्रह किया है कि महिला चिकित्सक के 51,97,329 रुपए के चिकित्सा बिल का भुगतान करने में मदद की जाए। चूंकि भागवनानी अपनी यादवाशत खो चुकी हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई रिश्वेदार आगे नहीं आया है, ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल एक अदालत मित्र नियुक्त किया जाता है कि वे अपने विल का भुगतान की अनुमानित एकलीपासी सुनिश्चित करने के लिए आदित्य नामांकित विल लेकर आवश्यक रिश्वेदार आगे नहीं आया है, ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल एक अदालत मित्र नियुक्त किया जाता है कि वे अपने विल का भुगतान की अनुमानित एकलीपासी सुनिश्चित करने के लिए आदित्य नामांकित विल लेकर आवश्यक रिश्वेदार आगे नहीं आया है, ऐसे में उच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछले साल एक अदालत मित्र नियुक्त किया जाता है कि वे अपने विल का भुगतान की अनुमानित एकलीपासी सुनिश्चित करने के लिए आदित्य नामांकित विल लेकर आवश्यक रिश्वेदार आगे नहीं आया है,

## खबर संक्षेप

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सभी के लिए प्रेरणादायी बने

फरीदाबाद। सेक्टर 82 स्थित

फ्लोरिडा सोसायटी में श्री कृष्ण

जन्माष्टमी पर बड़ी धूमधाम के साथ

मनाया गया।

सोसाइटी ने विधायक राजेश

नागर के बौतौर

मुख्य अतिथि

आमंत्रित किया।

जहां नागर ने

भगवान् श्री कृष्ण का अभिषेक

किया और लॉक मैगल के लिए

प्रार्थना की अपांडल्यूपी फ्लोरिडा

सोसायटी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी

सबसे अलग अंदाज व भव्य तरीके

से आयोजित की।

टोडेज ने काट ठोकने के बाद युवक से नारपीट

गरुग्राम। राजेंद्रा पार्क थाना एरिया

में द्वारा एक्सप्रेसवे पर रोडेज का

मामला सामन आया है। जिसमें

कैंटर चालक ने काट को ठोकने के

बाद अपने साथियों से मिलकर कार

चालक से जमकर मारपीट की।

घायल पीड़ित को दिल्ली के एक

अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली पुलिस ने वारदात रोकें

पार्क थाना पुलिस को दी। जिस पर

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू

कर दी।

28 अपराधियों के खिलाफ

जिलाबाद करवाई



गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस

कमिशनर रेपुलिस ने 26

अपराधियों को 6 माह के लिए

जिला बदर किया है। पुलिस का

कहना है कि वह लोग अपराधी

किस के लोग हैं और अपराध

करने के अध्यस्त हैं। इनकी

गतिविधियों से समाज में असांति

फैल सकती है। जिला बदर किए

जाने वालों में सूनो अपार त्यारी

, नांद, कूलरीप, इमरान आदि के

नाम शामिल है।

कबूतर पालने को लेकर

दोस्त को छाक से नार डाला

गाजियाबाद। थाना टीला मोड़

क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर को

कबूतर पालन कर दी। पुलिस में

दोस्त ने दूसरे दोस्त की छाक से

गोद कर हाना कर दी। पुलिस ने

आपराधी को गिरफतार कर लिया है।

एसीपी शानीमार्ग गार्डन सूर्य बली

मौर्य ने बताया कि अजय और

योगेंद्र कबूतर पालन करते थे। दोनों

के बीच विवाद हो गया। योगेंद्र ने

32 वर्षीय अजय रप्त चाक से

हमला कर दिया। अजय को

तक्कल शहदरा स्थित गुरु तेग

बहादुर अस्पताल ले जाया गया।

जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित

कर दिया।

चोटी के शक नें युवक को

पीट-पीट कर नार डाला

गाजियाबाद। थाना टीला मोड़

इलाके में चोटी के शक में युवक को

भीड़ ने पीटपीट का नार डाला।

पुलिस ने 3 को

गिरफतार किया है।

जबकि बाकी की

तलाज जारी है।

एसीपी सूर्यबली

मौर्य ने बताया

कि पुलिस को

डायल 112 के माध्यम से थाना

टीला मोड़ क्षेत्रान्तर्गत अनिल पुत्र

पप्पू का शब पड़ा होने की सूचना

मिली। पुलिस ने मोके पर पहुंचकर

शब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम

हेतु भिजवाया।

पुलिस ने 3 को

गिरफतार किया है।

जबकि बाकी की

तलाज जारी है।

एसीपी शक्तिवार्षी

के गांव डुबुआ के जर्जर तालाब के

जीर्णोद्धार के कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इसी कड़ी में आज गांव डुबुआ के जर्जर तालाब के

जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है जिसका

जीर्णोद्धार लगभग 80 लाख की लागत से किया

जायगा। इसके साथ ही गांव बाजारी के तालाब नम्बर-31 की भी वर्क आर्डर जारी हो गया है

जिसका कार्य लगभग 29 लाख 50 हजार की

लागत से होगा।

इस भौमि पर एसडीओ अमित चौधरी, दीन

दयाल नंबर-48 शामिल है।

एसआईटी विधानसभा के तालाबों की डीपीआर

बनकर काफी समय से लम्बित पड़ी थी लेकिन

कार्य होनी ही पा रही थी, इस मालकों के लेकर

विधानसभा सत्र मार्च 2021 में प्रसन संख्या

346 लगाया था। जिसपर सरकार ने जवाब

दिया था कि जल्द से जल्द तालाबों का

## स्कूल, कालेज, फैक्ट्री में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

हरिभूमि न्यूज़॥ फरीदाबाद

प्रदेश में महाला सुरक्षा को लेकर हरियाणा

पुलिस अब कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ

रही है। सेक्टर सिटी केन्द्र के तहत पुलिस द्वारा

स्कूल, कालेज, फैक्ट्री

में आयोजन

करने के लिए

प्रारंभिक

के तौर पर फिलहाल चुना गया

है। अब कामकाजी

महिलाओं

में भी आयोजन

करने के लिए

प्रारंभिक

के तौर पर

CRYPTO TO CLIMATE, INDIA EYES CONSENSUS AT THE G20 SUMMIT

# Delhi takes a step back to move forward

## Group must unite for swift action on green switch, says industry



SOUMYARENDRA BARIK & AANCHAL MAGAZINE  
New Delhi, September 8

**FROM CALLING FOR** a global framework on regulating crypto-assets to yielding on climate transition, India, as part of its G20 presidency, is working to evolve a consensus on a range of contentious issues even if that means stepping back on many of its stated position.

On Thursday, the International Monetary Fund (IMF) and the Financial Stability Board (FSB), released a policy paper, at the request of the Indian G20 Presidency, which recommended against an outright ban on crypto-assets. Instead, it suggested introducing a licensing regime for crypto-asset platforms bringing the asset under the fold of anti-money laundering and counter-terrorist financing standards.

India's expected endorsement shows how far its key regulators have moved: In 2018, the Central Board of Direct Taxes had submitted a draft scheme to the finance ministry for banning virtual currencies and a month later, the RBI restrained banks from dealing in cryptocurrencies, a decision that had to be reversed by the Supreme Court in 2020.

Despite this, the banking regulator has been vocal about its problems with crypto-assets, having identified them as "a macro-economic risk". In July last year, underscoring that the



"What India has signalled is that this is the beginning of the conversation on a global framework for regulating crypto-assets, with New Delhi acting as the main enabler, which in itself is a big win from our perspective," he added. The Sherpas of the G20 countries were in Manesar over the last three days, and their action will move to Delhi for the leaders' summit today (September 9) as they work on coming up with a joint communiqué so that the leaders' summit can produce a declaration.

### World Bank lauds India's DPI

**DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI)** has had a transformative impact on India, extending far beyond inclusive finance, according to a World Bank report, prepared in conjunction with the G20 Summit in New Delhi. The multilateral body cited "groundbreaking measures" taken by the Narendra Modi-led government and the pivotal role of government policy and regulation.

in shaping the DPI landscape, "India has achieved in just 6 years (on DPI) what would have taken about five decades," said the report.

The JAM Trinity (Jan Dhan, Aadhar and Mobile) has propelled financial inclusion rate from 25% in 2008 to over 80% of adults in last 6 years, a journey shortened by up to 47 years thanks to DPIs, the WB report said. — FE BUREAU

MANISH GUPTA  
New Delhi, September 8

**ENERGY SECTOR PLAYERS** want the G20 leaders to prepare a swift energy transition plan and scale up green financing to ensure a smooth transformation to clean solutions as early as possible.

India will host the 18th G20 Summit in New Delhi on 9th and 10th September. The two-day event will see participation from top world leaders.

"India's G20 presidency has provided us a unique opportunity to wield considerable influence in sculpting the contours of global policies on energy transition," said Praveer Sinha, Tata Power's chief executive officer (CEO) and managing director.

India should lead the transformative global effort by fostering ground-breaking technologies to accelerate clean and affordable energy transitions to enable sustainable and inclusive growth, he added.

Climate change, which has emerged as the foremost existential threat to the planet, has taken center stage at the ongoing G20 Summit, while green financing and energy transition have become a major subject of

India's G20 presidency has provided us a unique opportunity to wield considerable influence in sculpting the contours of global policies on energy transition

PRAVEER SINHA, TATA POWER CEO & MD

deliberations. "It is the need of the hour to prioritise swift action for a sustainable future. Accelerating the green transition demands a multi-faceted approach," ENGIE India managing director Amit Jain said.

Robust policies must incentivise renewable energy adoption and carbon reduction. Investment in innovative technologies is imperative to bolster energy efficiency and minimise environmental impact, he said.

The industry players believe that the world leaders must collaborate to address global warming and work towards equitable energy sources as soon as possible.

India leads with 42% renewable energy capacity, built over recent years with major contributions from solar



manufacturing to disposal post use, Prasad added.

"Producing green hydrogen and its derivatives in the wind and solar rich countries such as India and exporting these to those that lack the resource needs formalising through appropriate treaties on an urgent basis," he said.

"I believe the time to act is now and the solutions needed to accelerate are already available. Electrification and digitisation are the best vectors for sustainability and efficiency, playing a pivotal role in creating a more sustainable future," said Deepak Sharma, Greater India zone president and CEO and MD of Schneider Electric India.

A collaborative approach is the only way to create a climate-positive world for current and future generations, he noted.

The G20 energy ministers, in their Goa meeting last July, agreed to attain global net zero greenhouse gas emissions by 2050 and double the rate of improvement in energy efficiency by 2030.

World needs annual investment of over \$4 trillion at low-cost financing for energy transition, according to a G20 document.

To make energy storage scalable, strong policy support from the government and the global leaders must come together to set up a global financing mechanism to not just fund the well-established lithium-ion cell production but also accelerate R&D on commercially attractive storage solutions with a lesser carbon footprint in the entire value – from mining to

and wind energy. It plans to set up 500 giga watt (GW) green energy capacity by 2030.

"In order to ensure round the clock renewable energy and to address issues of intermittency and grid stability, there is an urgent requirement for comprehensive energy storage solutions," said Envision Wind Power Technologies India CEO RPV Prasad.

The industry players believe that the world leaders must collaborate to address global warming and work towards equitable energy sources as soon as possible.

India leads with 42% renewable energy capacity, built over recent years with major contributions from solar

will make it the 11th biggest economy of the world. So far its status has been invited international organisation at G-20. At the Bali edition of G-20 last year, some key members had shown support for the inclusion of the Union in G-20.

The Prime Minister (Narendra Modi), who is a great believer in the global south, has written to all the

leaders (of G-20) and there has been a very positive response but formally that will come at the summit," India's G-20 Sherpa Amitabh Kant said at a press briefing.

"All countries of G20 are proposing AU being included as a full member of the group. We expect that the summit proceedings starting tomorrow morning will make a suitable decision on it."

# More steps soon to boost supply of pulses: Govt

SANDIP DAS  
New Delhi, September 8

**THE CENTRE** aims to curb the spike in inflation of pulses through several measures such as abolition of import duties on certain varieties, long-term import commitments, imposition of stock holding limits and sale of surplus stocks in the open market.

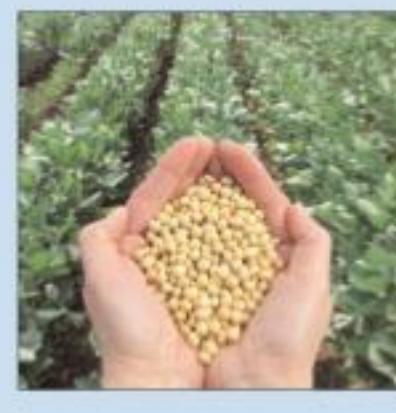
"We want to ensure that there are adequate supplies of pulses in the coming festive months from domestic arrivals and imports," Rohit Kumar Singh, secretary, department of consumer affairs told FE.

Retail inflation in the 'pulses and products' category in July was at 13.27%, which went up because of higher inflation in arhar (34.05%), moong (9.07%) and urad (7.85%). The pulses inflation had hit double digits in June at 10.53%. Earlier this week, the consumer affairs department had asked traders and importers to mandatorily disclose stocks of masur (lentils) and a suitable action would be taken under the essential commodities act if stocks are not declared.

Singh said at a time when the imports of lentils from Canada and tur (arhar) varieties of pulses from African countries have increased, few players are trying to 'manipulate' the market against the interests of the consumers.

"Through imports and imposition of stock holdings limits, we would like to ensure that pulses are available at reasonable prices," Singh said.

India imports lentils largely from Canada and Australia as domestic production is unable to match rising consumption of pulses. India signed a memorandum of understanding (MoU) with Mozambique for import of 0.2 million tonne (MT) of



### ENSURING SUPPLY

■ Removal of import duties, long-term import commitments and stock limits likely

■ Retail inflation in the 'pulses and products' category in July was at 13.27%

arhar annually for five years when the retail prices of tur skyrocketed to ₹200 a kg in 2016. This MoU was extended for another five years in September 2021.

In 2021, India entered into MoUs with Malawi and Myanmar for the import of 50,000 tonne and 0.1 MT of tur per annum, respectively, till 2025.

The import duty on tur, urad and masur has been abolished to improve domestic stocks. India has removed retaliatory additional duty imposed on the imports of chickpeas (10%) and lentils (20%) from the United States.

The country has been largely import dependent for three varieties of pulses – lentils, tur (pigeon pea) and urad (black gram).

In May, the government had imposed limits on the stocks of tur and urad dal till October 31.

Meanwhile, the government is likely to impose stock holding limits on chana (gram) due to the spike in prices in the last one month.

## African Union set to get G20 membership

MUKESH JAGOTA  
New Delhi, September 8



**AFRICAN UNION (AU)** President Azali Assoumani landed in New Delhi on Friday afternoon for participation in the G-20 Summit, where a decision is likely to be taken on making the grouping of 55 African nations a full member of the 20-nation economic block. The African Union

members have a combined GDP of \$2.26 trillion, which

will make it the 11th biggest economy of the world. So far its status has been invited international organisation at G-20. At the Bali edition of G-20 last year, some key members had shown support for the inclusion of the Union in G-20.

The Prime Minister (Narendra Modi), who is a great believer in the global south, has written to all the

leaders (of G-20) and there has been a very positive response but formally that will come at the summit," India's G-20 Sherpa Amitabh Kant said at a press briefing.

"All countries of G20 are proposing AU being included as a full member of the group. We expect that the summit proceedings starting tomorrow morning will make a suitable decision on it."

**The Indian EXPRESS**  
JOURNALISM OF COURAGE

**RELIGARE**  
Values that bind

Presents  
**The Indian EXPRESS AQDA**

Co-presented by

**ASG EYE HOSPITALS**



WHERE  
NEWSMAKERS  
DROP IN FOR  
A CANDID CHAT.

The Express Adda hosts

**Kareena Kapoor Khan**  
Actor

in conversation with

**Devyani Onial**  
National Features Editor  
The Indian Express

**Jyoti Sharma Bawa**  
Entertainment Editor  
The Indian Express

By invitation only



Associate Partner



Experience Partner

Use #ExpressAdda & join the conversation, live and exclusive on:

Indianexpress.com

twitter.com/IndianExpress

facebook.com/IndianExpress

### NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (COMMERCIAL DEPARTMENT)

PALIKA KENDRA, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001

#### PUBLIC NOTICE FOR CONSUMERS

Due to switching over of billing application to new platform by NDMC, the generation of water & electricity bill was affected. Now the water & electricity bills of billing cycle August, 2023 have been generated and are available on NDMC Web Portal ([https://ewbillimg.ndmc.gov.in/](http://ewbillimg.ndmc.gov.in/)) for download and payment. All water & electricity bill consumers of NDMC are informed to make their bill payments either online (Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI, BHIM etc.) or offline at the following NDMC Facilitation Centers.

• To update e-KYC with accurate mobile number and email address by visiting the link <https://online.ndmc.gov.in/ekyc/>.

• Opt e-bill to get incentive of Rs. 20/- per bill on electricity & water. Inconvenience caused is regretted.

Director (Commercial)  
New Delhi Municipal Council



**TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY**  
Moradabad  
Accredited with NAAC **A** Grade  
12-B Status from UGC

**FORM G (THIRD)**  
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST  
**M/S SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED OPERATING IN REAL ESTATE AT HARYANA**  
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

#### RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the Corporate Debtor along with PAN/CIN/LP No.	<b>SRS Real Infrastructure Limited CIN: L65910HR1990PLC040431</b>
2. Address of the registered office	SRS Multiplex, Top Floor City Centre, Sector-12 Faridabad, Haryana-121007
3. URL of website	<a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Faridabad, Rewari, Panchkula, Palwal, Rohtak (All places are in State of Haryana)
5. Installed capacity of main products/ services	Development and Construction of Commercial and Residential Projects.
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per the available, there is no operation of Corporate Debtor in last few years.
7. Number of employees/ workers	Nil
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	The required details can be sought by E-mail at <a href="mailto:cirp.srsreal@gmail.com">cirp.srsreal@gmail.com</a> by submitting the confidential undertaking.
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria can be downloaded from website <a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
10. Last date for receipt of expression of interest	<b>24-09-2023</b>
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	<b>04-10-2023</b>
12. Last date for submission of objections to provisional list	<b>09-10-2023</b>
13. Process email id to submit EOI	<a href="mailto:cirp.srsreal@gmail.com">cirp.srsreal@gmail.com</a>

Sd/-  
Amarpal  
Resolution Professional of SRS Real Infrastructure Ltd  
Regn. No.: IBB/IPA-001/PI/P-01584/2018-2019/12411  
AFA Valid Upto: 23.11.2023

Address: E-11, Lower Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi-110014

**FORM G (THIRD)****INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST****M/S SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED  
OPERATING IN REAL ESTATE AT HARYANA**

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**RELEVANT PARTICULARS**

1. Name of the Corporate Debtor along with PAN/CIN/LLP No.	<b>SRS Real Infrastructure Limited</b> CIN: L65910HR1990PLC040431
2. Address of the registered office	SRS Multiplex, Top Floor City Centre, Sector-12 Faridabad, Haryana-121007
3. URL of website	<a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
4. Details of place where majority of fixed assets are located	Faridabad, Rewari, Panchkula, Palwal, Rohtak (All places are in State of Haryana)
5. Installed capacity of main products/ services	Development and Construction of Commercial and Residential Projects.
6. Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	As per the available, there is no operation of Corporate Debtor in last few years.
7. Number of employees/ workmen	Nil
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	The required details can be sought by E-mail at <a href="mailto:cirp.srsreal@gmail.com">cirp.srsreal@gmail.com</a> by submitting the confidential undertaking.
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at	The eligibility criteria can be downloaded from website <a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
10. Last date for receipt of expression of interest	<b>24-09-2023</b>
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	<b>04-10-2023</b>
12. Last date for submission of objections to provisional list	<b>09-10-2023</b>
13. Process email id to submit EOI	<b>cirp.srsreal@gmail.com</b>

Date : 09.09.2023

Place: New Delhi

Sd/-

Amarpal

Resolution Professional of SRS Real Infrastructure Ltd

Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP/ P-01584/2018-2019/12411

AFA Valid Upto: 23.11.2023

Address: E-11, Lower Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi-110014

**ਛਾਰਮ ਜੀ (ਡੀਜ਼)**  
ਕੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਂਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ

**ਸੇਵਾ ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਰੀਅਲ ਇਨਡ੍ਰਾਸਟਰੀਜ਼ ਕਲਰ ਲਿਮਿਡ  
ਕੇਂਡਿਗਾਈਟ** ਦਿੱਤੇ ਰੀਅਲ ਮਾਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਹੈ  
ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਸੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਬੋਕਰਪਟਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ  
ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤਿਆ) ਵੇਖਾਲੇਸ਼ਨ, 2016 ਦੇ ਵੇਖਾਲੇਸ਼ਨ 36(੧) ਅਧੀਨ।

**ਸੱਥੀਤ ਦੇਰਦੇ**

1. ਪ੍ਰੈਸ/ਸੀਆਈਐਨ/ਅੰਲਾਨਿੰਗ ਨੰ. ਸੰਮੌਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਸਾਰ ਦਾ ਹੈ	ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਰੀਅਲ ਇਨਡ੍ਰਾਸਟਰੀਜ਼ ਕਲਰ ਲਿਮਿਡ CIN: L65910HR1990PLC040431
2. ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾਤਰ ਦਾ ਪਤਾ	ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਮਲਟੋਪਲੈਂਚਸ, ਸਿਖਹਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਿਟੀ ਸੈਟਰ, ਸੈਕਟਰ-12, ਹਰਿਹਾਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ-121007
3. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ	<a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a>
4. ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੇਵਵੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਲਾਉਰ ਵਿਵਾਸ਼ ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਸਥਿਤ ਹੈ	ਹਰਿਹਾਰਾਂ, ਰੋਹਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਹਤਗੜ੍ਹ (ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹਰਿਹਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ)
5. ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	ਕਮਰਸੀਅਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਕੇਸ਼ਪਸੈਟ
6. ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗ	ਉਪਲਬਧ ਅਤੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਥਟਰ ਦਾ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
7. ਵਰਕਰਾਂ/ਵਰਕਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੀ	ਨਿੱਜ
8. ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਟੋਰੋਟ (ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਮੌਤ) ਸੰਮੌਤ ਕ੍ਰੈਡੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੁਵਿੱਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵੈਂਡੋਟਸ ਤਾਂਦੀ ਸਾਂਘਰਤ ਅਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤਾਹੂੰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ :	ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ cirp.srsreal@gmail.com 'ਤੇ ਸੰਪਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਪਤ ਵਚਨਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਕੋਈ ਦੇ ਸੈਕਾਲ 2.5(2 X 6) ਅਧੀਨ ਹੈਸ਼ਲੋਸ਼ਨ ਕੋਪਲੈਕਿਟਸ ਲਈ ਪਾਰਵਰਾ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ :	ਥੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ <a href="https://srsrealinfracirp.in/">https://srsrealinfracirp.in/</a> ਤੋਂ ਇੱਕਨੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਕੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ	24-09-2023
11. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੈਸੇਲੂਸ਼ਨ ਵਿਨੋਕਾਰੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	04-10-2023
12. ਆਉਂਦੀ ਸਥੀ ਸਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ	09-10-2023
13. ਟੋਹਿਆਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਮੱਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੀ	cirp.srsreal@gmail.com

ਸ਼ਾਹੀ/-

ਅਮਰਪਾਲ

ਅੰਸ਼ਭਾਗ ਰੀਅਲ ਇਨਡ੍ਰਾਸਟਰੀਜ਼ ਕਲਰ, ਦਾ ਵੈਸੇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨ  
IBBI/IPA-001/IP-01584/2018-2019/12411

ਮਿਤੀ : 09.09.2023

ਸਥਾਨ : ਨਵੀਂ ਲਿੰਕੀ

ਪਤਾ : ਫੌ-11, ਸੰਭਰ ਰਾਹਾਂਡ ਟਾਊਨ, ਸੰਗਪੁਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਲਿੰਕੀ-110014

**ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ**  
RozanaSpokesman.com